



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० १२]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च २३, १९६८ (चैत्र ३, १८९०)

No. 12]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 23, 1968 (CHAITRA 3, 1890)

इस भाग में सिमन पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र ४ मार्च १९६८ तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 4th March 1968 :—

अंक Issue No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subjects
38	Budget 1968-69	—Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance—	29th Feb. 1968
39	No. F. 3 (3)-NS/68 dt. 29th Feb. 1968.	Ministry of Finance.	Amendments to the notification No. F. 3 (21)-2/NS/62, dt. 1st Nov. 1962 relating to 4½% Ten year Defence Deposit Certificates.
40	No. F. 3(5)-NS/68, dt. 29th Feb. 1968.	Do.	The Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) Amendment Rules, 1968.
41	No. 3(6)-NS/68, dt. 29th Feb. 1968.	Do.	Post Office (Fixed Deposits) Rules 1968.
42	No. 39-ITC (PN)/68, dt. 4th March, 1968.	Ministry of Commerce	Import Policy for Registered Exporters for the year 1967—March 1968—nomination of manufacturers of metallic yarn against export of Natural Silk Fabrics, Garments and made-up articles.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियाँ प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी।
मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुँच जाने चाहिए।

Copies of the *Gazette Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these *Gazettes*.

विषय सूची (CONTENTS)

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर)
भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम
न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर
नियमों, विनियमों तथा आदेशों और
संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

253

भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर)
भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम
न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी
अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों
आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

309

	पृष्ठ		पृष्ठ
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	19	भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	121
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	231	भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ-लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	229
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—	भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	105
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—	भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	37
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	539	भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	109
भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	1581	भाग IV —गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	53

पूरक संख्या 12—

16 मार्च 1968 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट	449
24 फरवरी 1968 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े	461

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolution issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	Page 253
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	309
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	19
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	231
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (1)—General Statutory Rules, (including orders, bye-laws, etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministries of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	539

PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	Page 1581
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	121
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	229
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	105
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	37
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	109
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	53
SUPPLEMENT No. 12— Weekly Epidemiological Reports for week-ending 16 March 1968	449
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 24 February 1968	461

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 1968

सं० 19-प्रेज०/68—राष्ट्रपति, दिनांक 11 फरवरी, 1967 के भारतीय राजपत्र के भाग 1, अनुभाग 1 में प्रकाशित इस सचिवालय की अधिसूचना सं० 15-प्रेज०/67, दिनांक 26 जनवरी, 1967 में “समर सेवा स्टार 1965” सम्बन्धित प्रतिष्ठापन में जिसे दिनांक 6 मई, 1967 के भारतीय राजपत्र के भाग 1, अनुभाग 1 में प्रकाशित इस सचिवालय की अधिसूचना सं० 38-प्रेज०/67 दिनांक 29 अप्रैल, 1967 द्वारा संशोधित किया गया था, पंचम परिच्छेद के अन्तर्गत अनुच्छेद (ख) के (i), (ii) एवं (iii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करने का आदेश देते हैं :—

“(ख) (i) कार्मिक जिन्होंने 6 सितम्बर, 1965 और 25 जनवरी 1966 के बीच अरब सागर के क्षेत्रों में जिनका विवरण बाद में दिया जाएगा, समुद्री-टोह लेने के लिए भारतीय नौसेना के जहाजों पर कम से कम दस दिन की अवधि के लिए सेवा की हो;

(ii) कार्मिक जिन्होंने 6 सितम्बर, 1965 और 25 जनवरी, 1966 के बीच समुद्री क्षेत्रों पर, जिनका विवरण बाद में दिया जाएगा, नीचे संकेतानुसार सांग्रामिक उड़ानों की हों :—

(1) समुद्री-टोह लेने के लिए सीहाक हवाई जहाज के वायुसेना वायु-स्क्वाड्रन के एक कर्मिंदल के सदस्य के रूप में कम से कम तीन सांग्रामिक उड़ानों की हों अथवा कुल पांच घण्टे की सांग्रामिक उड़ान की हो;

(2) समुद्री-टोह लेने के लिए एलाइज हवाई जहाज के नौसेना वायु-स्क्वाड्रन के एक कर्मिंदल के सदस्य के रूप में कम से कम तीन सांग्रामिक उड़ानों की हों अथवा कुल दस घण्टे की सांग्रामिक उड़ानों की हों।

(iii) उन विशेष क्षेत्रों में, जो सेना तथा वायुसेना के लिए निर्धारित हैं, समुद्री तट पर तैनात नौसेना कार्मिक “समर सेवा स्टार 1965” के उन्हीं शर्तों पर पात्र होंगे जो सेना तथा वायुसेना कार्मिकों पर गैला है। और

(iv) नौसेना कार्मिक जो सेना अथवा वायुसेना से सम्बद्ध होंगे, सेवाओं की उन शर्तों के अनुसार जिनसे वे सम्बद्ध हैं, पदक प्राप्त करने के पात्र होंगे।

नागेन्द्र सिंह, राष्ट्रपति के सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-11, दिनांक 12 फरवरी 1968

सं० 9/21/67-पी० IV—भारतीय राजपत्र के भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशित इस मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 9/21/67-पुलिस IV दिनांक 25-4-1967 में क्रम संख्या 214 पर “एस० एन० पटनायक” के स्थान पर “एस० एम० पटनायक” पढ़ा जाएगा।

जी० एस० कपूर, अवर सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 8 मार्च 1968

संकल्प

सं० 8/2/67-एच०एस०एस०—इस मन्त्रालय के तारीख 5 दिसम्बर, 1967 के संकल्प सं० 8/2/67-हि० सं० स० के अधीन गठित केन्द्रीय हिन्दी समिति में श्री जी० सुब्रह्मण्यम, अब सदस्य नहीं रहे हैं, उनके स्थान पर भारत सरकार श्री एम० एस० मूर्ति, संसद् सदस्य को समिति के सदस्य के रूप में सहर्ष नियुक्त करती हैं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सब राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों, भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों और विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, मन्त्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मन्त्री सचिवालय, योजना आयोग, नियन्त्रक और महालेखा परीक्षा, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

के० पी० मिश्र, उप सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 1968

संकल्प

सं० एफ० 14 (9) प्लॉट (ए)/66—पार्टिनी टी एस्टेट, जो भारत सरकार द्वारा खरीदा गया है और जिसका प्रबन्ध उसके निमित्त मैसर्स आक्टाविवस स्टील एंड कं० लि०, कलकत्ता द्वारा

किया जा रहा है, के प्रबन्ध को ठीक ढंग से चलाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने, इस मन्त्रालय के संकल्प सं० 14(9) प्लांट (ए)/66 दिनांक 30-3-1966 द्वारा बनाए गए सलाहकार बोर्ड को, उक्त एस्टेट के प्रबन्ध एवं संचालन से सम्बन्धित सभी मामलों में सरकार को मन्त्रणा देने के लिए, पुनर्गठित करने का निश्चय किया है।

2. पुनर्गठित बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

- (1) श्री ए० के० राय
अध्यक्ष, टी बोर्ड,
14, ब्रेवार्न रोड,
कलकत्ता-1 अध्यक्ष
- (2) श्री सुमत प्रसाद
5 तथा 7 नेताजी सुभाष रोड
कलकत्ता-1 सदस्य
- (3) श्री आर० महादेवन
उपसचिव, भारत सरकार
वित्त मन्त्रालय,
नई दिल्ली। सदस्य
- (4) श्री० बी० कृष्णमूर्ति
अवर सचिव, भारत सरकार
वाणिज्य मन्त्रालय
नई दिल्ली। सदस्य
- (5) श्री डब्ल्यू० एच० जी० वेयर्ड,
प्रबन्ध निदेशक,
मैसर्स आक्टावियस स्टील एंड
कं० लि०, 14, ओल्ड कोर्ट
हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता। सदस्य

3. प्रबन्ध अभिकर्ता मैसर्स आक्टावियस स्टील एंड कं० लिमिटेड, कलकत्ता, एस्टेट के प्रबन्ध से सम्बन्धित सभी नीति विषयक मामलों बोर्ड के समक्ष रखेंगे और बोर्ड इन मामलों पर विचार करेंगे तथा उनके विषय में सरकार को मन्त्रणा देगा।

4. बोर्ड का गठन 31 जनवरी, 1969 तक की अवधि के लिए है और इस की बैठकें सामान्यतः कलकत्ता में होंगी।

एस० वनजी, उप-सचिव

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 1968

संकल्प

सं० 1(95)/67-ए० ई० (इण्ड)-1—भारत में निर्मित मोटर कारों की किस्म के बारे में दूर तक फैली हुई शिकायतों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 15 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने संकल्प दिनांक 11 जुलाई, 1967 में श्री जी० पाण्डे की अध्यक्षता में निम्नलिखित बातों के बारे में जांच-पड़ताल और सिफारिशें करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी :—

(क) मोटरकारों की किस्म में कहां तक गिरावट आई है, उसकी परिस्थितियां और कारण क्या हैं;

(ख) क्या कार निर्माताओं द्वारा कच्चे माल, पुर्जों और कुछ ऐसे पुर्जों को जोड़ कर जिन्हें उन्होंने खरीदा है या उनका निर्माण किया है तथा पुर्जे जोड़ कर तैयार की गई कारों के बारे में किस्म के निम्नतम मानक निर्धारित किए हैं और उनका सुनिश्चय किया है;

(ग) क्या उनको उपलब्ध उपकरण, सुविधाएं तथा प्रबन्ध पर्याप्त हैं और उपयुक्त परीक्षण एवं निरीक्षण में उनका कारगर इस्तेमाल किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में इससे अधिक अच्छा निरीक्षण और किस्म नियन्त्रण का सुनिश्चय करने के लिए उनकी अतिरिक्त आवश्यकताएं क्या हैं,

(घ) इस गिरावट में देशी, सहायक तथा अन्य उद्योगों का क्या स्थान है और उनमें सुधार करने के लिए क्या कार्रवाई की जानी है;

(ङ) गारंटियों की किस्म की प्रभावोत्पादकता तथा विक्रेताओं एवं अन्य संबद्ध व्यक्तियों द्वारा बिक्री के पश्चात् की गई मरम्मतता की पर्याप्त और तत्परता तथा अन्त में—

(च) इन मामलों में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाने आवश्यक और सम्भव होंगे।

2. समिति ने अपनी रिपोर्ट 1 दिसम्बर, 1967 को प्रस्तुत कर दी थी। इसमें मोटर कार से संबंधित तथा अन्य उद्योगों के कार्य-मंचालन का विशद अध्ययन किया गया है जिसमें देश में निर्मित कारों की किस्म में गिरावट के कारणों, कारों तथा अन्य सहायक वस्तुओं के निर्माताओं द्वारा किस्म नियन्त्रण संबंधी कार्यविधियों की कमियों, उचित संगठन के अभाव, तकनीकी ज्ञान, उपकरण तथा परीक्षण संबंधी सुविधाओं की अपर्याप्तता एवं ठीक किस्म के और पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल आदि मिलने से संबंधित कठिनाईयों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। समिति ने भिन्न-भिन्न प्रकार की खराबियों को दूर करने तथा देश में निर्मित मोटर कारों की किस्म में सुधार करने के लिए भी सिफारिशें की हैं।

विभिन्न सिफारिशों का सारांश तथा उन पर किए गए सरकार के निर्णय अनुबन्ध में दिए गए हैं।

3. सिफारिशों को लागू करने में उद्योग, सरकार तथा विक्रेताओं को सम्मिलित रूप से विस्तृत कार्रवाई काफी समय तक करनी पड़ेगी। इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कि आवश्यक सुधार शीघ्रता से किए जाते हैं, सरकार का विचार सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए उठाए गए कदमों की समय-समय पर समीक्षा करने की व्यवस्था करने का है।

4. समिति द्वारा विभिन्न समस्याओं का विशद अध्ययन करने तथा व्यावहारिक और ठोस सिफारिशें करने के लिए सरकार उसकी अत्यधिक प्रशंसा करती है।

आदेश

आदेश दिया गया कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित मन्त्रालयों की भेजी जाए तथा इसे भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

एन सुब्रह्मण्यम, विशेष सचिव

अनुबन्ध

क्रम समिति की सिफारिशें सरकार का निर्णय संख्या

कार निर्माताओं के संबंध में

1. प्रबन्धकों को किस्म के संबंध में पूर्णतया जागरूक होना चाहिए और यह जागरूकता उन्हें समय-समय पर भाषणों, प्रदर्शनों पुस्तिकाएं परिचालित करके, पुरस्कार एवं प्रोत्साहन के द्वारा अपने सभी स्तर के कर्मचारियों और मजदूरों में भरनी चाहिए।
2. प्रबन्ध से संबंधित कर्मचारियों को किसी सुगठित संस्था में आधुनिक व्यवस्था तकनीक में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
3. निरीक्षण तथा किस्म नियंत्रण तकनीक से सम्बन्धित विभागों में नियुक्त कर्मचारियों के लिए समय-समय पर आयोजित पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के साथ-साथ निरीक्षण एवं किस्म नियंत्रण की तकनीक में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाने चाहिए।
4. प्रत्येक संयंत्र में पूर्ण योग्यता प्राप्त कर्मचारियों के अधीन एक अलग निरीक्षण विभाग स्थापित किया जाना चाहिए जो उच्च प्रबन्धकों के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी हो।
5. उपयुक्त योग्यता वाले कर्मचारियों से युक्त एक अलग किस्म नियंत्रण विभाग होना चाहिए।
6. प्रत्येक संयंत्र में एक कम्पनी मानक विभाग होना चाहिए जो भारतीय मानक संस्था से सम्पर्क रखे और कम्पनी के अपेक्षित मानक निर्धारित करें।
7. तीनों संयंत्रों द्वारा उपयुक्त निरीक्षण और सांख्यिकीय नमूना कार्यविधि तथा

स्वीकार कर ली गई। उद्योगपतियों में कहा जाएगा कि वे स्वयं इस पर चर्चा करें और निश्चित समय के अन्दर सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए एक सम्मिलित कार्यक्रम प्रस्तुत करें।

क्रम समिति की सिफारिशें सरकार का निर्णय संख्या

सांख्यिकीय किस्म नियन्त्रण विधियां तैयार करके उन्हें अपनाया जाना चाहिए।

8. देश में आने वाले कच्चे माल और पुर्जों का उन्हें जोड़ कर तैयार करने से लेकर अन्तिम रूप दिए जाने वाले निरीक्षण में सांख्यिकीय नियंत्रण के तरीके अपनाए जाने चाहिए।

9. कच्चे माल, पुर्जों, सांख्यिकीय किस्म नियंत्रण के तरीकों तथा परीक्षण कार्यविधियों के भारतीय मानकों का, जहां कहीं विद्यमान हों, पालन किया जाना चाहिये। आई० एस० आई० प्रमाणीकरण चिह्न वाले कच्चे माल और पुर्जों जहां कहीं उपलब्ध हों, खरीदे जाने चाहिये।

स्वीकार कर ली गई। उद्योगपतियों को निदेश दिये जायेंगे कि वे इस प्रयोजन के लिये निर्धारित विशिष्ट विवरण, मानक तथा परीक्षण संबंधी, कार्यविधियां भारतीय मानक संस्था में प्राप्त करें तथा वही सामान खरीदे जो आई० एस० आई० प्रमाणीकरण चिह्न में शामिल हो।

10. प्रत्येक संयंत्र में कच्चे माल तथा पुर्जों के परीक्षण के लिये पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिये।

11. कार्य करने के लिये आवश्यक वस्तुएं तथा खरीदे गये पुर्जों कितने समय तक चलेंगे इसकी जांच करने के लिये परीक्षण करने लगाये जाने चाहिए। परीक्षण कारों तथा परीक्षण मार्गों पर खरीदे हुए पुर्जों के नमूनों का भी निरन्तर परीक्षण किया जाना चाहिये। इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त संख्या में परीक्षण कारें नियत कर दी जानी चाहिये।

स्वीकार कर ली गई। कार निर्माताओं को निदेश दिये जायेंगे कि वे उपकरणों आदि का आयात करने के लिये आवश्यक सहायता प्राप्त करने के बारे में सरकार से कहें और परीक्षण के जो वरसे उनके पास हैं उनके बारे में बतायें तथा छः महीने के अन्दर व्यक्तिगत अथवा संयुक्त रूप में उसमें वृद्धि करने के बारे में अपने विचार भी सरकार को बतायें।

12. जब कभी अधिक सामान और पुर्जों की आवश्यकता उत्पन्न हो तो कार निर्माताओं के कुछ विभागों की रूप-रेखा का पुनरीक्षण किया जाना

स्वीकार कर ली गई। निर्माताओं को निदेश दिये

क्रम संख्या	समिति की सिफारिशें	सरकार का निर्णय	क्रम संख्या	समिति की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
	चाहिये तथा इस संबंध में होने वाले दोहरे काम को रोका जाना चाहिये।	जायेंगे कि वे सिफारिशों को कार्यान्वित करें और उनके पालन करने की पुष्टि करें।			कर लें, और उसके बाद ही उस संहिता का कड़ाई से पालन किया जाय।
13.	पुर्जों के फिर से डिजाइन तैयार करने, नये डिजाइनों का विकास करने तथा उनमें सुधार करने की दृष्टि से खराबियों का विश्लेषण करने के लिये प्रत्येक संयंत्र में एक अनुसन्धान तथा विकास अनुभाग स्थापित किया जाना चाहिये।		18.	विक्रेताओं को कारों का सम्भरण करने के पूर्व सभी कारों का निर्माताओं द्वारा सम्भरण-पूर्व पूर्ण निरीक्षण किया जाना चाहिए।	स्वीकार कर ली गई। निर्माताओं तथा विक्रेताओं से कहा जायेगा कि वे सम्भरण-पूर्व निरीक्षण रिपोर्ट तथा पालन की प्रक्रिया निर्धारित करें। कार का विवरणात्मक इतिहास रखा जाना चाहिए।
14.	उपलब्ध फालतू उपकरण क्षमता का इस्तेमाल अन्य संयंत्रों/सहायक उत्पादकों द्वारा किये जाने की अनुमति दी जानी चाहिये।	निर्माताओं से कहा जायेगा कि वे इस बात पर विचार करें क्योंकि उपकरणों का अधिकतम इस्तेमाल करना स्वयं उनके हित में होगा।	19.	काई भी कार, जिसमें पुर्जों की कमी हो, विक्रेताओं को न बेची जाय और कार के साथ उप-युक्त किस्म के निर्धारित औज़ार भी हों।	स्वीकार कर ली गई। उत्पादकों को निदेश दिया जायेगा कि वे कार के साथ सम्भरण किए जाने वाले कल-पुर्जों तथा औज़ारों का निश्चित उल्लेख करें।
15.	सहायक सामान निर्माताओं को कार निर्माता के संयंत्र में परीक्षण संबंधी सुविधाओं उपलब्ध होने के साथ-साथ उन्हें मानक संबंधी विस्तृत एवं विशिष्ट बातें भी बताई जानी चाहिये।	स्वीकार कर ली गई। निर्माताओं को इसके अनुसार निदेश दिये जायेंगे।	20.	उत्पादक के संयंत्र से विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों तक ले जाते समय कारों को अति तीव्र गति पर चलाने को न्यूनतम करने के लिये कारों में छेड़े न जा सकने वाले गति नियंत्रक लगाए जाने चाहिए।	स्वीकार कर ली गई। उद्योगपतियों को ऐसा करने के लिए परामर्श दिया जायेगा।
16.	कार निर्माता, सहायक सामान निर्माता तथा उनके सम्भरण-कर्ताओं के बीच लम्बी अवधि के आधार पर किये जाने वाले उपयुक्त और सामान खरीदने और भुगतान नीति तथा ठेके संबंधी करार निर्धारित कर दिये जाने चाहिये। इन करारों में स्थिरता लाने की दृष्टि से पालन न किये जाने पर जुर्माने तथा मुआवजे की व्यवस्था लागू की जानी चाहिये।	स्वीकार कर ली गई। उद्योगपतियों को निदेश दिये जायेंगे कि वे सहायक सामान बनाने वालों के एसोसियेशन तथा सघु उद्योगों के विकास आयुक्त से बात-चीत करें और छः महीने के अन्दर क्रय की समान नीति ढूंढ निकालें।	21.	कार रखने की अधिक लागत को रोकने तथा कल-पुर्जों की समयनुकूल मरम्मत के लिए उपयुक्त प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए।	
17.	सारे माल को उपयुक्त निरीक्षण तथा परीक्षणोपरांत ही स्वीकार किया जाना चाहिये, पिछले सम्भरण अथवा मार्क के आधार पर नहीं।	स्वीकार कर ली गई। उद्योगपतियों को निदेश दिए जायेंगे कि वे सम्भरण-कर्ताओं के परामर्श से निरीक्षण तथा परीक्षण की विस्तृत संहिता तैयार	22.	यात्री कारों की कुशलता के बारे में आंकड़े इकट्ठे करने की उचित प्रणाली बनाई जानी चाहिए ताकि शिकायतों, खराबियों और असफलताओं से सम्बन्धित जानकारी का विश्लेषण तथा उनमें सुधार करने के लिये की गई कार्रवाई उत्पादकों तक पहुंचाई जा सके।	स्वीकार कर ली गई। निर्माताओं से कहा जायेगा कि वे आपस में तथा अपने विक्रेताओं से विचार-विमर्श करके कुशलता के बारे में जानकारी दिये जाने की समान प्रणाली अपनाएं।
			23.	वह गारन्टी जिसके साथ कार बेची जाती है, 12 महीने अथवा 16,000 किलोमीटर की दूरी जो भी पहले हो,	स्वीकार कर ली गई। उत्पादकों को इसका पालन करने के लिए निदेश दिए जायेंगे।

क्रम संख्या	समिति की सिफारिशें	सरकार का निर्णय	क्रम संख्या	समिति की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
	समान रूप से मान्य होनी चाहिये। सभी खराबियां जो दोषपूर्ण निर्माण अथवा कारीगरों के कौशलहीन होने के कारण रह गई हों उनका सुधार तथा इस अवधि में खराब पुर्जों को बदलने तथा उनसे संलग्न खर्चा ग्राहक पर बिना खोझ डाले किया जाना चाहिये।		28.	कार उत्पादकों को कुछ पुर्जों, जिन्हें सहायक उत्पादक बना सकते हैं, का उत्पादन छोड़ देने के लिए राजी किया जाना चाहिए।	स्वीकार कर ली गई है। निर्माताओं को ऐसा करने का परामर्श दिया जायेगा।
			सहायक उद्योगों के सम्बन्ध में		
24.	कार उत्पादकों को रद्द किए गए माल तथा पुर्जों की बिक्री आदि की प्रक्रिया भी बनानी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह दुबारा उनके कारखाने में प्रयुक्त नहीं किये जायेंगे।	स्वीकार कर ली गई। उत्पादकों को 6 महीने के अन्दर-अन्दर ऐसी प्रक्रिया बनाने तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई सरकार को सूचित करने के लिए कहा जायेगा।	1.	प्रबन्धकों को किस्म के प्रति पूर्णतया जागरूक होना चाहिए और ऐसी जागरूकता संचार उन्हें अपने सभी स्तर के कर्मचारियों में समय-समय पर भाषणों, प्रदर्शनों, पुस्तिकाएं परिचालित करके, पारितोषिक तथा प्रोत्साहन के माध्यम से करना चाहिए।	
25.	कार उत्पादकों तथा सहायक पुर्जों के निर्माताओं को यथा-सम्भव अधिक से अधिक ऐसे पुर्जों का विकास करना चाहिए जो तीनों कारों में लगाए जा सकें ताकि उत्पादिता बढ़े, लागत कम हो और किस्म में सुधार हो सके।	स्वीकार कर ली गई। उत्पादकों को तुरन्त कार्यवाही करने और इसके पालन के बारे में सरकार को सूचित करने के लिए कहा जायेगा।	2.	प्रबन्धक वर्ग को एक मुगठिन संस्था में आधुनिक प्रबन्ध प्रणाली के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।	
26.	उत्पादकों में समय-समय पर विक्रेताओं की वर्कशापों का निरीक्षण करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो जाये कि मूल सामान के रूप में जो फालतू पुर्जे दिए जाते हैं उनके गारन्टी की अवधि में ही प्रयोग के लिए स्टॉक किया जाता है।	स्वीकार कर ली गई। उद्योगपतियों को इस सिफारिश का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा जायेगा।	3.	निरीक्षण तथा किस्म नियन्त्रण प्रणालियों के बारे में भी इन विभागों में नियुक्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और इसके साथ-साथ समय-समय पर पुनश्चर्चा पाठ्यक्रमों का आयोजन भी किया जाना चाहिए।	स्वीकार कर ली गई। अखिल भारतीय मोटर गाड़ी तथा सहायक उद्योग संघ से अनुरोध किया जायेगा कि वह इन विषयों पर सहायक एककों से बातचीत करके एक सर्वमान्य प्रथा का निर्धारण
27.	जब किसी आवश्यक नाजुक पुर्जे में खराबी का पता चले तो उस वर्ग से बेची गई सभी कारों के स्वामियों को तुरन्त विक्रेता की वर्कशाप में पहुंचाने तथा अपनी कार का निरीक्षण तथा मरम्मत कराने के लिये सूचित किया जाना चाहिए।	स्वीकार कर ली गई। उद्योगपतियों को इस सिफारिश का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा जायेगा।	4.	प्रत्येक एकक में पूर्ण योग्यता प्राप्त कर्मचारियों के अधीन एक पृथक निरीक्षण विभाग खोला जाना चाहिये और वह उच्च प्रबन्धकों के लिये ही उत्तरदायी हो।	
			5.	पूर्ण योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के अधीन एक पृथक किस्म नियन्त्रण विभाग होना चाहिए।	
			6.	प्रत्येक एकक में समवाय मानक विभाग स्थापित किया जाना चाहिए जो	

क्रम संख्या	समिति की सिफारिशें	सरकार का निर्णय	क्रम संख्या	समिति की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
	भारतीय मानक संस्था से सम्पर्क रखे और समवाय मानकों का निर्धारण करे।				विचार कर लेना चाहिये ताकि जहां तक सम्भव हो सके, दोहरी व्यवस्था को रोका जा सके।
7.	उपयुक्त निरीक्षण तथा सांख्यिकीय विश्लेषण की क्रिया तथा सांख्यिकीय किस्म नियन्त्रण की विधियों का निर्धारण किया जाना चाहिये ताकि प्रत्येक एकक उसे अपना सके।	करें और छः मास के भीतर इनको लागू करने की योजना बनाएं।	11.	कार्य करने के लिये आवश्यक वस्तुएं तथा पुर्जों कितने समय तक चलेंगे, इसका पता लगाने के लिये परीक्षण बरमे लगाये जाने चाहिये।	स्वीकार कर ली गई। सहायक एककों को तदनुसार कार्य करने के लिये निर्देश दिये जायेंगे।
8.	कारखाने में आने वाले कच्चे माल तथा अधीन पुर्जों के निरीक्षण से लेकर उत्पादों के अन्तिम रूप तक किए जाने वाले निरीक्षण में सांख्यिकीय किस्म नियन्त्रण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिये।		12.	प्रत्येक एकक में पुर्जों के नये नमूने तैयार करने तथा वर्तमान नमूनों को नया रूप देने, खराबियों को सुधारने की दृष्टि से विश्लेषण करने के लिये एक अनुसन्धान तथा विकास अनुभाग होना चाहिये।	स्वीकार कर ली गई। सहायक निर्माताओं को इस सिफारिश को लागू करने तथा इस पर की गई कार्यवाही सरकार को सूचित करने के लिये कहा जायेगा।
9.	कच्चे माल तथा अधीन पुर्जों के भारतीय मानक सांख्यिकीय किस्म नियन्त्रण विधियों, तथा परीक्षण संबंधी कार्य-विधियाँ, जहां कहीं भी विद्यमान हों, का पालन किया जाना चाहिए। जहां तक उपलब्ध हो सकें कच्चा माल तथा अधीन पुर्जों, जिन पर भारतीय मानक संस्था के प्रमाणीकरण चिह्न अंकित हों, खरीदे जाने चाहिये।	स्वीकार कर ली गई। अखिल भारतीय मोटर गाड़ी तथा सहायक उद्योग संघ से कहा जायेगा कि वे इस मामले को भारतीय मानक संस्था के सामने रखें और कच्चे माल, अधीन पुर्जों, परीक्षण प्रक्रिया आदि के जो भारतीय मानक निर्धारित किए जा चुके हैं उन्हीं को प्राप्त करें और भारतीय मानकों को चिह्नित करने की वर्तमान प्रणाली को लागू करें।	13.	सहायक उद्योगों तथा उनके सम्भरणकर्ताओं के बीच ठेके के करारों, खरीद तथा उसकी अदायगी की उचित तथा समान नीति का निरूपण किया जाना चाहिये।	स्वीकार कर ली गई। निर्माताओं को इसे अखिल भारतीय मोटरगाड़ी तथा सहायक उद्योग संघ स्तर पर इस सिफारिश पर विचार करने और सहायक निर्माताओं तथा उनके सम्भरणकर्ताओं के माध्यम से ठेकों, खरीद तथा अदायगी की समान नीति के निरूपण के लिये अनुरोध किया जायेगा। और लघु उद्योग क्षेत्र में स्थापित एककों से खरीद पर भी उसी नीति का पालन किया जाना चाहिये जिसके लिये संघ को लघु उद्योगों के विकास आयुक्त से बातचीत करनी चाहिये।
10.	प्रत्येक एकक के पास कच्चे माल तथा अधीन पुर्जों के परीक्षण की पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिये। विकल्पतः जहां भी सम्भव हो, कुछ सहायक एकक मिलकर संयुक्त परीक्षण की व्यवस्था कर लें जिसका लाभ वे सभी उठा सकें।	स्वीकार कर ली गई। प्रत्येक सहायक एकक को अपने यहां उपलब्ध कच्चे माल की परीक्षण सुविधाओं को आंकने तथा ऐसी अतिरिक्त सुविधाओं, जो कि वह स्थापित करने का विचार रखता हो, की एक सूची तैयार करने के निर्देश दिए जायेंगे। इस पर संघ के स्तर पर भी	14.	सारे माल को उपयुक्त निरीक्षण तथा परीक्षणोपरान्त ही स्वीकार किया जाना चाहिये पिछले सम्भरण अथवा मार्क के आधार पर नहीं।	स्वीकार कर ली गई। निर्माताओं से तदनुसार कार्यवाही करने के लिये कहा जायेगा।
			15.	कारों के पुर्जों की कुशलता के बारे में आंकड़े इकट्ठे करने की	स्वीकार कर ली गई। निर्माताओं से कहा जायेगा

क्रम संख्या	समिति की सिफारिश	सरकार का निर्णय	क्रम संख्या	समिति की सिफारिश	सरकार का निर्णय
7.	विक्रेता को कार इस्तेमाल करने वालों से प्राप्त शिकायतों का उपयुक्त रिकार्ड रखना चाहिये।		5.	रेल द्वारा कई कारों को ले जाने वाले विशेष प्रकार के दो टायर वाले माल डिब्बों का निर्माण करने के कार्य में शीघ्रता की जानी चाहिये।	स्वीकार कर ली गई। रेल मंत्रालय से उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये निवेदन किया जायेगा।
सरकार के सम्बन्ध में					
1.	भारतीय मानक संस्था से निवेदन किया जाना चाहिये कि वह कच्चे माल और पुर्जों का कार निर्माताओं, सहायक सामान निर्माताओं तथा उनके सम्भरणकर्ताओं की सहायता से प्राथमिकता के आधार पर मानक तैयार करे।	स्वीकार कर ली गई। भारतीय मानक संस्था से निवेदन किया जायेगा कि वह विभिन्न वस्तुओं की दी गई प्राथमिकताओं के अनुसार मांग तैयार करने के लिये कार्यवाही शुरू कर दे। निर्माताओं के प्रतिनिधि भी इस कार्य से सम्बद्ध होंगे। प्राथमिकता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित कार्य को 12 महीने के अन्दर पूरा करने के लिये प्रयत्न किये जाने चाहिये।	6.	सरकार को चाहिये कि वह सहायक सामान बनाने वाले उन निर्माताओं की सहायता देना बन्द कर दे, जिनका माल निरन्तर निर्धारित स्तर से नीची किस्म का होता है और इसमें सुधार करने के लिये कार्रवाई करे। यदि उनका कोई विशेशी सहयोग हो तो उसके नवीकरण के लिये भी उन्हें अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।	स्वीकार कर ली गई।
	जान चाहिये कि अब भी कोई भारतीय मानक तैयार कर लिये जाते हैं, तो वे उन्हें अपनाएँ और कार्यान्वित करें।	स्वीकार कर ली गई। उद्योगपतियों को निदेश दिये जायेंगे कि जब भी कोई ऐसे मानक तैयार हो जायें तो वे उन्हें अपना लें।		तीनों कार निर्माताओं को निवेदन दिये जाने चाहिये कि वे कारों को एक गारंटी के साथ बेचें जो समान रूप से 12 महीनों की अवधि अथवा 18,000 किलोमीटर की दूरी जो भी पहले हो, तक के लिये मान्य होना चाहिये। सभी खराबियाँ जो दोषपूर्ण निर्माण अथवा कारीगरों के कौशलहीन होने के कारण रह गई हों, उनका सुधार तथा इस अवधि में खराब पुर्जों को बदलने तथा उनसे संलग्न खर्च ग्राहक पर बोझ डाले बिना किया जाना चाहिये।	स्वीकार कर ली गई। निर्माताओं को तबनुसार कार्रवाई करने के लिये निदेश दिये जायेंगे।
3.	आई० एस० आई० प्रमाणीकरण चिह्न योजना स्थापित की जाने वाली प्राथमिकताओं के आधार पर सहायक सामान बनाने वाले सभी निर्माताओं के लिये अनिवार्य कर दी जानी चाहिये।	भारतीय मानक संस्था से कहा जायेगा कि वह सहायक सामान निर्माताओं के परामर्श से प्राथमिकता प्राप्त वस्तुओं की एक सूची बनाएँ और इन वस्तुओं के बारे में आई० एस० आई० चिह्नांकन योजना अनिवार्य की जा सकती है।	8.	इस बात का सुनिश्चय करने के लिये कि कार निर्माताओं तथा सहायक सामान निर्माताओं द्वारा ऊपर बताई गई सम्बद्ध सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं, कार निर्माता के संयंत्रों तथा सहायक सामान निर्माताओं के एककों में व्यक्ति-	सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली गई। इस प्रकार का संगठन स्थापित करने की विस्तृत योजना आगे कार्रवाई करने के लिये तैयार की जायेगी।
4.	सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों को निदेश दिये जाने चाहिये कि वे इस उद्योग के लिये जितनी भी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता हो, अपेक्षित किस्म का कच्चा माल उपलब्ध करावें।	स्वीकार कर ली गई। लोहा तथा इस्पात विभाग से निवेदन किया जायेगा कि वह संबंधित संघों द्वारा प्रत्येक वर्ग की आवश्यकताओं और उनकी मात्रा के बारे में सूची तैयार किये जाने के बाद उपयुक्त कदम उठाये।			

क्रम संख्या	समिति की सिफारिश	सरकार का निर्णय	क्रम संख्या	समिति की सिफारिश	सरकार का निर्णय
	गत अथवा सामूहिक रूप से जैसा भी आवश्यक समझा जाये, लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने चाहिये जिससे विरम की गिरावट को रोका जा सके और ग्राहकों को किसी प्रकार का कष्ट दिये बिना काम किया जा सके ।		12.	सरकार कार निर्माताओं तथा सहायक सामान निर्माताओं पर लगाये गये करों में, निरीक्षण तथा किस्म नियंत्रण पर किये गये व्यय के अनुपात में छूट देने पर भी विचार कर सकती है ।	इस सिफारिश की वित्त मंत्रालय के परामर्श से जांच की जायेगी ।
9.	अपेक्षित किस्म के उसी प्रकार के कच्चे माल/पुर्जों खरीदने के लिये विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई जानी चाहिये जो इस समय देश में उपलब्ध नहीं है और बाहर के देशों में उनके व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिलाने में सहायता की जानी चाहिये ।	स्वीकार कर ली गई ।	13.	कार चलाने के लाइसेंस मंजूर करने से पूर्व सरकार को कार चलाने के अधिक कड़े परीक्षण कर देने पर विचार करना चाहिये ।	स्वीकार कर ली गई ।
10.	सरकार कार निर्माताओं को 'डी लक्स माडल' की कारें बनाने के लिये उनके मूल्य एवं वितरण पर नियंत्रण लगाये बिना अनुमति देने, उसका प्रौद्योगिक विकास करने के लिये आवश्यक प्रोत्साहन देने की व्यवस्था करने तथा इस समय देश में जो कारें बनाई जा रही हैं, उनकी किस्म में सुधार करने पर विचार कर सकती है ।	अन्य सभी सिफारिशों को कार्यान्वित किये जाने के पश्चात् इस सिफारिश की जांच की जायेगी ।	विषय		
11.	सरकार को मोटर गाड़ी उद्योग के लिये एक सहकारी अनुसन्धान तथा विकास संगठन की शीघ्र ही स्थापना करने में सहायता करनी चाहिये जिसके लिये सिद्धान्त रूप में सहमति दी जा चुकी है । जब तक यह संगठन स्थापित नहीं होता तब तक के लिये कार निर्माताओं की प्रतिरक्षा मंत्रालय में कारों का परीक्षण करने के लिये उपलब्ध सुविधाओं का इस्तेमाल करने देना चाहिये ।	स्वीकार कर ली गई । भारतीय मोटर गाड़ी निर्माता संघ से कहा जायेगा कि वह इस प्रकार के अनुसन्धान संगठन की शीघ्र ही स्थापना करे और इस बात का सुनिश्चय करने के लिये कदम उठाये जायेंगे कि छः महीने के अन्दर निश्चित प्रगति हुई है । कार निर्माताओं को ये निर्देश भी दिये जायेंगे कि वे प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं का इस्तेमाल करें ।			
			1.	कार खरीदने के लिये रजिस्ट्रेशन कार निर्माता के प्रादेशिक प्रतिनिधि के पास कराया जाना चाहिये और ग्राहकों को उस विक्रेता का नाम बताना चाहिये जिसके द्वारा कार स्वीकार की जायेगी ।	स्वीकार कर ली गई ।
			2.	मजदूरों के लिये काम करने की उपयुक्त दशाओं, पर्याप्त सुख-सुविधाओं, पुरस्कारों तथा प्रोत्साहनों की व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे उनमें किस्म के बारे में जागरूकता का संचार किया जा सके ।	स्वीकार कर ली गई । निर्माताओं को तदनुसार परामर्श दिया जायेगा ।
			3.	रंग-रोगनों की किस्म में सुधार किया जाना चाहिये । रबड़ के ऐसे उपयुक्त पुर्जों का विकास किया जाना चाहिये जो देश की कड़ी वायुमण्डलीय स्थितियों को सहन कर सकें । प्लेट कांच बनाने के काम में शीघ्रता की जानी चाहिये और जब तक ऐसा नहीं हो जाता, तब तक के लिये कठोर निरीक्षण तथा किस्म नियंत्रण के तरीके अपनाये जा सकते हैं ।	स्वीकार कर ला गई । रंग-रोगनों तथा रबड़ के पुर्जों की किस्म सुधारने के लिये कदम उठाये जायेंगे और जहां कहीं आवश्यक समझा जायेगा अपेक्षित सीमा में आयात के लिये भी अनुमति दी जायेगी । हवा से बचने वाले प्लेट ग्लास का आयात हो रहा है और तब तक आयात किया जाता रहेगा जब तक देश में इसके उद्योग का विकास नहीं हो जाता ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय**(कृषि विभाग—भा० कृ० अनु० परि०)**

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च 1968

सं० 28(1)/67-सी०डी०एन० (1)—भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की नियमावली के नियम 75 में की गई व्यवस्थाओं के अन्तर्गत, खाद्य तथा कृषि मन्त्री निम्नलिखित व्यक्तियों को इस सोसाइटी में कृषि अर्थशास्त्र, सांख्यिकीय तथा विपणन अनुसन्धान की स्थाई समिति का सदस्य 15 नवम्बर, 1966 से तीन वर्ष की अवधि तक अथवा जब तक समिति में उनके उत्तराधिकारी मनोनीत किए जाएं, जो भी अवधि पहले समाप्त हो, प्रसन्नतापूर्वक नियुक्त करते हैं :—

(1) उप-महानिदेशक (फसल विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली।

(2) उप-महानिदेशक (मू० सस्य विज्ञान तथा इंजीनियरिंग) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली।

(3) उप-महानिदेशक (पशु विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली।

(4) उप-महानिदेशक (शिक्षा तथा केन्द्र व प्रदेशों के सम्बन्ध), भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली।

पी० एस० हरिहरन, उप-सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 11th March 1968

No. 19-Pres./68.—The President is pleased to direct that in Notification No. 15-Pres./67, dated 26th January 1967, relating to the institution of Samar Seva Star 1965, published in Part I, Section 1, of the Gazette of India dated 11th February 1967, as amended by President's Secretariat Notification No. 38-Pres./67, dated 29th April 1967, published in Part I, Section 1, of the Gazette of India dated 6th May 1967, the following shall be substituted for paragraphs (b) (i), (ii) and (iii) under clause Fifthly :—

“(b) (i) Personnel who served for a minimum period of ten days aboard ships of the Indian Navy, in areas of the Arabian sea, to be specified later, for maritime reconnaissance between 6th September 1965 and 25th January 1966;

(ii) Personnel who carried out operational sorties, as indicated below, over the areas of the sea, to be specified later, between 6th September 1965 and 25th January 1966 :—

(1) A minimum of three operational sorties or a total of five operational flying hours as members of crew of the Naval Air Squadron of Seahawk aircraft for maritime reconnaissance;

(2) A minimum of three operational sorties or a total of ten operational flying hours as members of crew of the Naval Air Squadron of Alize aircraft for maritime reconnaissance;

(iii) Naval personnel based ashore in qualifying areas, as prescribed for the Army and Air Force, will be eligible for Samar Seva Star 1965 on the same conditions as applicable to Army and Air Force personnel; and

(iv) Naval personnel attached to the Army or Air Force would be eligible for the award according to the conditions of eligibility applicable to the service to which they were attached.”

NAGENDRA SINGH, Secy. to the President

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**CORRIGENDA**

New Delhi-11, the 12th February 1968

No. 9/21/67-P.IV.—In this Ministry's Notification No. 9/21/67-P.IV dated the 25th April 1967, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, read 'S. M. Patnaik' for 'S. N. Patnaik, appearing at S. No. 214.

The 8th March 1968

No. 9/63/66-P.IV.—In this Ministry's Notification No. 9/63/66-P.4 dated the 12th October, 1966, substitute S. No. "61" for S. No. "60", Serial Nos. "698 to 762, 764 to 782", for Serial Nos. "698 to 782" and Serial Nos. "847 to 857, 859 and 860" for Serial Nos. "847 to 860".

G. S. KAPOOR, Under Secy.

New Delhi-1, the 6th March 1968

No. 1/1(1)67-ANL.—The President is pleased to make the following amendment in the rules regulating the constitution and procedure of the Advisory Council associated with the Administrator, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands, published in this Ministry's Notification No. 71/36(2)(i)57-ANL dated June 29, 1957, namely :—

In the said rules.—

(i) for rule (1) the following shall be substituted, namely :—

“(1) The Advisory Council will consist of :—

(a) the Administrator, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands, who will preside over the meetings of the Council;

(b) non-official members of the Advisory Committee associated with the Minister of Home Affairs, including the Member of Parliament representing the Union Territory of Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands; and

(c) three other non-official members to be nominated by the President for a term of one year from the 1st of April of each year.”

(ii) rule (2) shall be omitted.

2. This amendment shall take effect from April 1, 1968.

A. D. PANDE, Jt. Secy.

New Delhi-1, the 8th March 1968

RESOLUTION

No. 8/2/67-H.S.S.—The Government of India have been pleased to appoint Shri M. S. Murti, M.P. as member of the Central Hindi Committee constituted under this Ministry's Resolution No. 8/2/67-H.S.S. dated the 5th September, 1967 in place of Shri G. Subramaniam who has ceased to be a member.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments, Administrators of Union Territories, all the Ministries and Departments of the Government of India, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General, Accountant General, Central Revenue, New Delhi, the Lok Sabha Secretariat and the Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. P. MISRA, Dy. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 7th March 1968

RESOLUTION

No. LEI(B)-47(7)/66.—In partial modification of the erstwhile Ministry of Industry's Resolution No. LEI(B)-47(7)/66 dated the 3rd March, 1967, read with Resolution No.

LEI(B)-47(7)/66 dated 4-7-1967 and subsequent Resolution of the same number dated 8-8-67, regarding the constitution of the Panel for the Air-conditioning and Refrigeration Industry, the following change in respect of the Panel given therein is being made with immediate effect—

The name at S. No. 17 of the Resolution is to be read as L. Charat Ram, Managing Director, Shriram Refrigeration Industries, instead of Shri B. K. Shreshta.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

D. R. SUNDARAM, Jt. Secy.

MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING & URBAN DEVELOPMENT

(Department of Family Planning)

New Delhi, the 13th March 1968

RESOLUTION

No. 1-13/67-C&C(FP).—The Government of India are pleased to appoint the Director, Central Health Education Bureau as a member of the National Family Planning Mass Education Advisory Committee constituted *vide* Ministry of Health, Family Planning and Urban Development, Department of Family Planning Resolution No. 1-13/61-C&C (FP) dated the 29th December, 1967.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. N. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture—ICAR)

New Delhi, the 12th March 1968

No. 28(1)/67-CDN.(I).—Under the provisions of Rule 75 of the Rules of the Indian Council of Agricultural Research, the Minister of Food and Agriculture has been pleased to nominate the following to be members of the Standing Committee for Agricultural Economic and Statistical and Marketing Research of the Society for a period of three years with effect from the 15th November, 1966, or till such time as their successors are nominated by him on the Committee, whichever period expires earlier :—

1. Deputy Director General (Crop Sciences), Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.
2. Deputy Director General (Soils, Agronomy & Engineering), Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.
3. Deputy Director General (Animal Sciences), Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.
4. Deputy Director General (Education & Centre-State Relations), Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.

P. S. HARIHARAN, Dy. Secy.

